IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ : मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन''

डॉ० अंजू कुमारी

व्याख्याता, ग्रामीण अर्थशास्त्र

पंडित तारणी झा कॉलेज, बाँका

शोध सार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ''नींव की ईंट'' की तरह है जो स्वतः दिखाई न पड़ने के बावजूद महल के निर्माण में आधारभूत तत्व का काम करता है। वर्ष–2010 में गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाते वक्त विश्व ने भारत को एक 'महाशक्ति' के रूप में देखा है। भारत में तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था, तकनीकी विशेषज्ञों की भारी–भरकम समृद्ध युवा–वर्ग, अशांत पड़ोसियों से घिरा शांतप्रिय देश, स्थिर आदर्श लोकतान्त्रिक सरकार और इस जैसे–अनेक सार्थक–कारक हमारे गणतंत्र के शुक्लपक्ष में चार चाँद लगा रहे हैं। भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक समस्या है; विशेष कर ग्रामीण समाज में जहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहाँ बेरोजगारी का रूप अतिभयावह हैं। ग्रामीण बेरोजगारी ने ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को भी प्रभावित किया है।

शब्द कुंजी : ग्रामीण, रोजगार, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी

भूमिका :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ''नींव की ईंट'' की तरह है जो स्वतः दिखाई न पड़ने के बावजूद महल के निर्माण में आधारभूत तत्व का काम करता है। वर्ष–2010 में गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाते वक्त विश्व ने भारत को एक 'महाशक्ति' के रूप में देखा है। भारत में तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी अर्थव्यवस्था, तकनीकी विशेषज्ञों की भारी–भरकम समृद्ध युवा–वर्ग,

अशांत पड़ोसियों से घिरा शांतप्रिय देश, स्थिर आदर्श लोकतान्त्रिक सरकार और इस जैसे–अनेक सार्थक–कारक हमारे गणतंत्र के शुक्लपक्ष में चार चाँद लगा रहे हैं।

दुनियाँ बूढ़ी हो रही है और भारत जवान। हमारी दो तिहाई आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनियाँ के आने वाले वक्त में यह युवा आबादी और बढ़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाला समय भारत का होगा। यही वजह है कि हमारी सरकार, हमारा व्यापार–तंत्र और हमारे योजनाकार लगातार सोच रहें हैं कि कैसे इतनी बड़ी आबादी को राष्ट्र–निर्माण के काम में लगाएँ ?

आँकड़े बताते हैं कि भारत के 47.00 प्रतिशत लोगों की उम्र बीस साल से कम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2015 तक यह 55.00 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। दुनियाँ में भारत को आज आर्थिक शक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका महत्वपूर्ण पक्ष युवा–शक्ति और युवा वर्ग है। वर्ष–2005 में युवाओं की (15–24 वर्ष) की आबादी चीन में–22 करोड़, भारत में–21 करोड़, अमेरिका में–4 करोड़, पाकिस्तान में–3 करोड़ तथा रूस में–25 करोड़ था। वर्ष–2020 के लगभग भारत में औसत उम्र 29 वर्ष, चीन में 37 वर्ष, अमेरिका में 37 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होने के अनुमान हैं यानी दस साल बाद भारत में युवाओं का ही बोल–बाला होगा। कल–तक बेरोजगारी समस्या बनी हुई थी मनुष्य के लिए, जनसंख्या के लिए, लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गईं हैं। इक्कीसवीं सदीं में मनुष्य समस्या है, जनसंख्या समस्या है– बेरोजगारी के लिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : यह कार्यक्रम अक्टूबर–1980 में प्रारम्भ किया गया था। पूर्व में संचालित ''काम के बदले अनाज कार्यक्रम'' को पुनर्गठित करके इसका नाम ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम'' रखा गया। 01 अप्रैल, 1989 से इस कार्यक्रम को ''जवाहर रोजगार योजना'' में सन्निहित कर दिया गया। पुनः इसे ''जवाहर ग्राम समृद्धि योजना'' के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 1999 में शामिल किया गया। तत्पश्चात यह कार्यक्रम ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम'' (नरेगा) के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो वर्ष–2010 में ''महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम'' (मनरेगा) के नाम से संचालित है।

रोजगार प्राप्त करने की समस्या आज विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी की समस्या के आलोक में दो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण अतिआवश्यक है–पहली, सामाजिक–आर्थिक समस्याओं की अवधारणा का तथा दूसरी सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा का। इस संदर्भ में पहली बात यह है कि ये अवधारणाएँ स्थैतिक नहीं होतीं, बल्कि ये गत्यात्मक होतीं हैं। दूसरी बात यह है कि हर युग में बेरोजगारी की समस्याएँ उस विशिष्ट–युग की ''शिशु'' होतीं हैं।

बेरोजगारी : जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे, ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परन्तु उसे कोई काम न मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार तथा इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अर्थात बेरोजगारी वह दशा है जिसमें

शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को, जो कार्य करने की इच्छा रखता है परन्तु प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम करने का अवसर नहीं मिलता है।

आर्थिक चिन्तन के इतिहास में बेरोजगारी के अवधारणा की विवेचन के कई सोपान रहे हैं, जहाँ क्लॉसिकल अर्थशास्त्रियों ने ''बेरोजगारी'' की अवधारणाओं को अपने सिद्धान्तों से पूर्ण बहिष्कृत कर पूर्ण रोजगार की सामान्य दशा को मान्यता दी, वहीं कीन्स ने प्रथम बार, तीसा की महान् मंदी के सन्दर्भ में, अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ''जेनरल थ्योरी'' में न्यून–रोजगार संतुलन का विवेचन किया। ''कीन्स'' का सर्वाधिक प्रमुख अवदान यह रहा है कि इन्होंने समाज के आर्थिक चिन्तन एवं आर्थिक सिद्धान्त को ''पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता'' के कटघरे से निकालकर इसे ''बेरोजगारी एवं अल्प–बेरोजगारी'' की ठोस तथा वास्तविक धरातल की मान्यता पर आधारित कर स्थापित किया।

लेकिन ''कीन्स'' का बेरोजगारी के सन्दर्भ में विवेचन विकासशील देशों के सन्दर्भ में न तो प्रासंगिक है और न ही उपयोगी। भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की बहुलता होती है एवं कृषि ही इनका मुख्य–आधारगत पेशा। चक्रिय बेरोजगारी की समस्या इन देशों के लिए प्रमुख समस्या नहीं होती है। अतः कीन्सीयन विश्लेषण के यंत्रों द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी तथा इसकी प्रकृति का विश्लेशण नहीं किया जा सकता। ग्रामीण समाज में इसके विश्लेषण के लिए यह अनिवार्य है कि हम निर्धनता एवं बेरोजगारी को ''सगी बहनों'' की तरह मानें और इसके निराकरण के लिए नितांत भिन्न नीति–यंत्रों को प्रयोग में लाएँ।

भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याएँ सबसे अधिक व्यापक है, भयावह है और सबसे अधिक गहन भी। इसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि यह ''खुली बेरोजगारी'' के रूप में प्रगट नहीं होती। इसका स्वरूप प्रच्छन्न होता है; यह अल्प–रोजगार के रूप में स्पष्ट होता है और इसकी प्रकृति ''छिपी हुई बेरोजगारी'' की होती है।

भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक समस्या है; विशेष कर ग्रामीण समाज में जहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहाँ बेरोजगारी का रूप अतिभयावह हैं। ग्रामीण बेरोजगारी ने ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण समाज में बेरोजगारी की समस्या एक अभिशाप है; इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण समाज में बेरोजगारी का दायरा दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है; क्योंकि इससे आर्थिक विकास की गति अति मंद पड़ जाती है, वहीं दूसरी ओर यदि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तो अर्थ–व्यवस्था में व्यापक सुधार होता है। इस तरह बेरोजगारी की वृद्धि से देश का सामाजिक–आर्थिक विकास अवरूद्ध होता है तथा समाज में असन्तोश, बेकारी और पलायन की प्रवत्ति बढ़ने लगती है।

बेरोजगारी का स्वरूप : इक्कीसवी सदीं के भारत में बेरोजगारी का अलग–अलग स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे बेरोजगारी के प्रकार या वर्गीकरण भी कह सकते हैं; जो वर्तमान समय में निम्न रूपों में पायी जाती हैं।

संरचनात्मक बेरोजगारी : जब देश में पूँजी के साधन सीमित होते हैं तो काम चाहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है तो ऐसे में बहुत–से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इस तरह के बेरोजगारी को ही ''संरचनात्मक बेरोजगारी'' कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का यही स्वरूप ज्यादा देखने को मिलता है।

प्रच्छन्न बेरोजगारी : किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होते हैं, तो उसे ''प्रच्छन्न बेरोजगारी'' कहा जाता है। बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, जैसे–ग्रामीण भारत के अन्तर्गत कृषि–कार्य में इस तरह की बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। प्रो0 नर्क्से के अनुसार– "अल्पविकसित देशों में कृषि–क्षेत्र में कार्यरत बहुत से खेतीहर मजदूर ऐसे होते हैं, जिन्हें यदि हटा दिया जाए तो न कृषि–कार्य बाधित होगा और न ही कृषि उत्पादन में कोई कमी होगी अर्थात कृषि उत्पादन में इनका योगदान शून्य के बराबर रहता है। ऐसे खेतीहर मजदूर आर्थिक दृष्टि से बेकार कहलाएगें, क्योंकि वे उत्पादन कार्य में नहीं लगे हुए हैं। इसलिए उन्हें बेरोजगार कहना अधिक उपयुक्त होगा। चूंकि देखने में ये श्रमिक कार्य में लगे होते हैं, इसलिए इनकी बेरोजगारी छिपी रहती है।" ऐसे बेरोजगारों का वास्तविक अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन इस बात से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और यह भी कि यदि ऐसे लोगों को कृषि–कार्य से निकाल दिया जाय, तो सम्भवतः कृषि–उत्पादन में कोई कमी नहीं आयेगी। इतना ही नहीं इससे शेष लोगों में काम की सक्रियता बढ़ेगी। ए0 के0 सेन का मत है कि "प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति कार्यकारी घण्टों की कम संख्या का रूप धारण कर लेती है।" ऐसे ग्रामीण व्यक्ति ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं।

खुली बेरोजगारी : खुली बेरोजगारी के अन्तर्गत श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के ही बेकार रहना पड़ता है। उन्हें थोड़ा–बहुत भी काम नहीं मिलता है। भारत में बहुत से श्रमिक गाँवों से शहरों की ओर काम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किन्तु काम उपलब्ध न होने के वहाँ वे बेरोजगार पड़े रहते हैं।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ''नींव की ईंट'' की तरह है जो स्वतः दिखाई न पड़ने के बावजूद महल के निर्माण में आधारभूत तत्व का काम करता है। भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक–आर्थिक समस्या है; विशेष कर ग्रामीण समाज में जहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहाँ बेरोजगारी का रूप अतिभयावह हैं। ग्रामीण बेरोजगारी ने ग्रामीण समाज के आर्थिक विकास को भी प्रभावित किया है। ग्रामीण समाज में बेरोजगारी की समस्या एक अभिशाप है; इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण समाज में बेरोजगारी का दायरा दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है; क्योंकि इससे आर्थिक विकास की गति अति मंद पड़ जाती है, वहीं दूसरी ओर यदि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तो अर्थ–व्यवस्था में व्यापक सुधार होता है।

इस तरह बेरोजगारी की वृद्धि से देश का सामाजिक–आर्थिक विकास अवरूद्ध होता है तथा समाज में असन्तोश, बेकारी और पलायन की प्रवत्ति बढ़ने लगती है।

संदर्भ सूची :

- त्रिपाठी, रेणु (2017) : ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली
- कुरूक्षेत्र मई, 2018
- कुरूक्षेत्र जून, 2017
- कुरूक्षेत्र जनवरी, 2004
- योजना फरवरी, 2018